

Title: Urged the Government to reduce the administrative expenditure of the Coal India Limited.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोल इंडिया लिमिटेड की कई अनुंगी कम्पनियों के घाटे बढ़ रहे हैं। इसका कारण प्रबंधन की अकुशलता है। खर्च और गलत डाटा दिखाकर गुमराह करने की पद्धति बनी हुई है। अनुंगी कम्पनियों के शीर्ष अधिकारी इतने सक्षम होते हैं कि किसी प्रकार की जांच को अपने पक्ष में कर लेते हैं।

लोक सभा महापंचायत है, लेकिन लगता है कि इसमें भी कुछ कहने पर असर नहीं होता है। भ्रष्ट और अकुशल इस महापंचायत की बात से डरते नहीं हैं। तभी तो स्पेशल मैन्शन के अधीन जनता की बात रखने या प्रश्न के माध्यम से जनहित का मामला उठाने पर विभाग को ही मान्य होती है। भविष्य के लिए यह संकेत काफी पीड़ादायक साबित होगा।

मेरा सरकार से आग्रह है कि सी.आई.एल. की अनुंगी कम्पनियों का CIL में एकीकरण किया जाये इससे प्रशासनिक खर्च में कमी होगी और अधिकारियों की संख्या में भी कमी आएगी। साथ ही सदन में उठाए गये मामले की एक निष्पक्ष अभिकरण द्वारा जाँच सुनिश्चित कराई जाए।